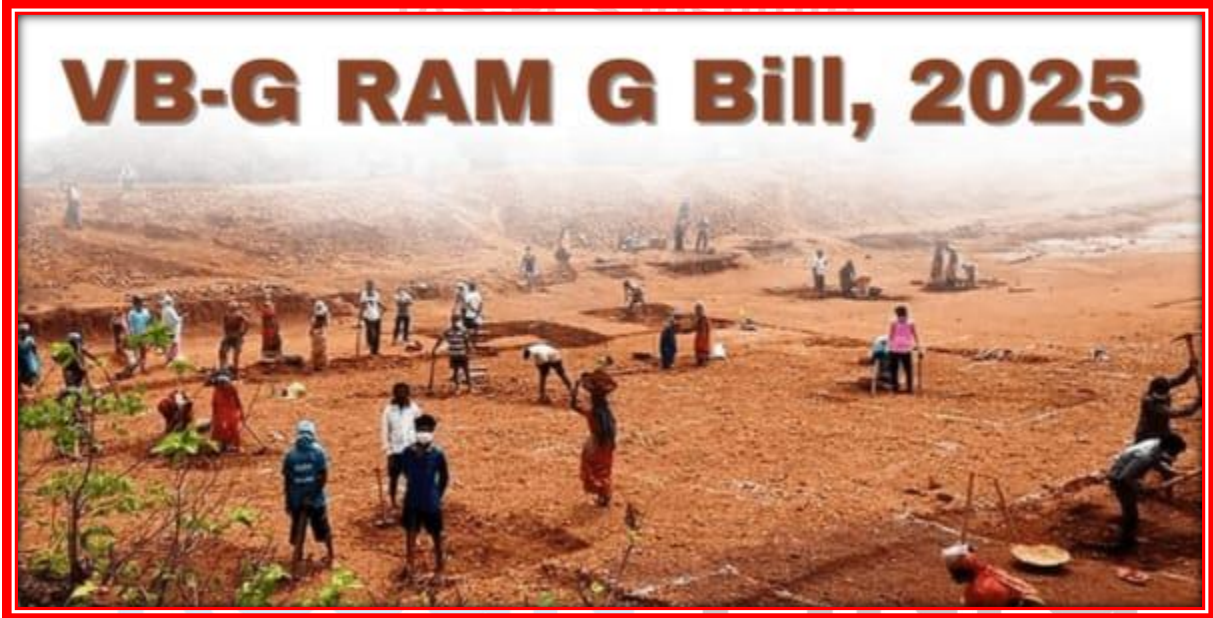


रिश्ताते और भी खराब:

VB-G RAM G विधेयक को लेकर बढ़ती चिंताएँ

UPSC प्रासंगिकता: GS Paper 2: संघवाद (Federalism), केंद्र-राज्य संबंध, शासन सुधार, ग्रामीण विकास नीतियाँ।



चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' यानी **VB-G RAM G विधेयक** पेश किया गया है, जो 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (MGNREGA) का स्थान लेगा। आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक मनरेगा (MGNREGS) के मूल चरित्र को मौलिक रूप से बदल देता है, जिससे विकेंद्रीकरण, राज्य की स्वायत्तता और ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों को नुकसान पहुँच सकता है।

पृष्ठभूमि (Background)

मनरेगा, जो कि एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना है, वर्ष 2005 में ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। गांधीजी की 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा पर आधारित यह योजना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रिया और मांग-आधारित (demand-driven) ढांचे पर जोर देती है।

VB-G RAM G विधेयक के मुख्य प्रस्ताव:

- योजना का नाम बदलना।
- रोजगार के दिनों को प्रति वर्ष 100 से बढ़ाकर 125 करना।

- आपूर्ति-आधारित (supply-driven) आवंटन प्रणाली शुरू करना
- इसे 'केंद्र प्रायोजित योजना' (Centrally Sponsored Scheme) बनाना, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का फंडिंग पैटर्न होगा
- केंद्र सरकार को प्राथमिक निर्णय लेने वाली संस्था बनाना

प्रमुख चिंताएँ

1. संघवाद को कमजोर करना: यह विधेयक आवंटन और निर्णयों पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करता है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता कम होती है। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने इसे अपने हितों पर अतिक्रमण बताते हुए इसका विरोध किया है।

2. मांग-आधारित प्रकृति से विचलन: मूल मनरेगा एक 'नीचे से ऊपर' (bottom-up) और मांग-आधारित योजना है। VB-G RAM G इसे आपूर्ति-आधारित दृष्टिकोण में बदल देता है, जहाँ आवंटन की एक सीमा (cap) होगी और अतिरिक्त खर्च का बोझ राज्यों पर पड़ेगा।

3. राज्यों पर वित्तीय बोझ: मूल योजना में 100% मजदूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती थी। नई योजना के तहत, राज्यों को लागत साझा (60:40) करनी होगी, जिससे पहले से ही वित्तीय दबाव झेल रहे राज्यों की स्थिति और खराब हो सकती है।

4. गांधीजी का प्रतीकात्मक विलोपन: योजना के नाम से गांधीजी का नाम हटाना 'ग्राम स्वराज' और स्थानीय लोकतंत्र के साथ जुड़े वैचारिक लिंक को कमजोर करता है, जो मूल मनरेगा की आत्मा थी।

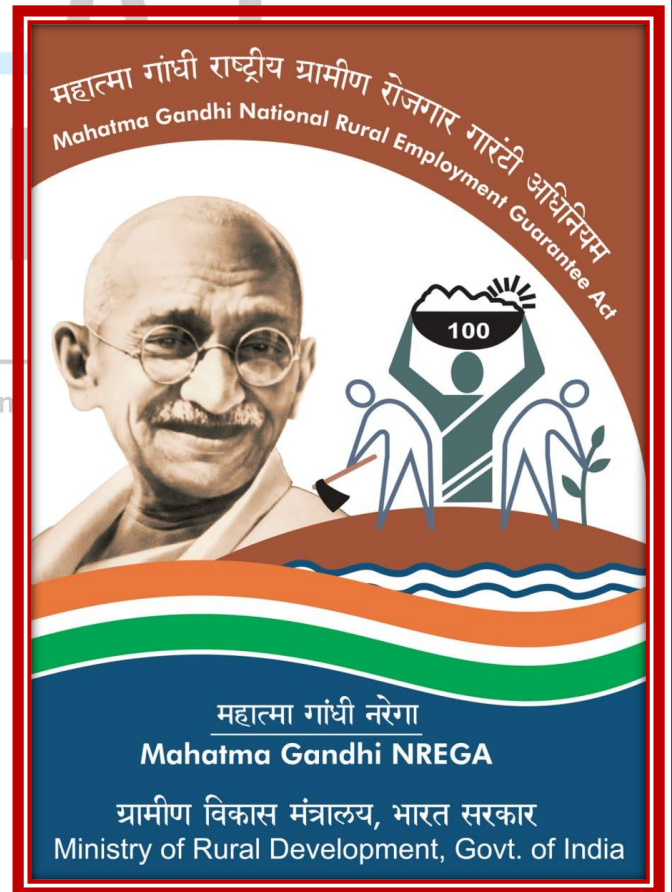
5. रोजगार की वास्तविकता: आंकड़े बताते हैं कि हाल के वर्षों में केवल 7-9.5% परिवारों ने ही मनरेगा के तहत पूर्ण रोजगार प्राप्त किया है। पर्याप्त राज्य प्रोत्साहन के बिना, यह नया मिशन ग्रामीण परिवारों को सार्थक काम देने में विफल हो सकता है।

संभावित प्रभाव (Implications)

- ग्रामीण भारत में विकेंद्रीकृत शासन का क्षरण।
- केंद्रीय आवंटन पर राज्यों की निर्भरता में वृद्धि।
- ग्रामीण मजदूरी और रोजगार सुरक्षा में संभावित गिरावट।
- ग्राम स्वराज की लोकतांत्रिक भावना और 'राम राज्य' के लोकाचार को ठेस पहुंचना।

आगे की राह (Way Forward)

- मनरेगा के मांग-आधारित और 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण को बरकरार रखा जाए।



- योजना की रूपरेखा और कार्यान्वयन में राज्यों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जाए
- ग्रामीण आजीविका की रक्षा के लिए मजदूरी के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण जारी रखा जाए
- प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन लागू करने से पहले राज्यों और स्थानीय निकायों के साथ परामर्श किया जाए
- गांधीजी और ग्राम स्वराज के साथ प्रतीकात्मक और वैचारिक संबंध को सुरक्षित रखा जाए

निष्कर्ष

VB-G RAM G विधेयक ग्रामीण रोजगार की पहुंच बढ़ाने का प्रयास तो करता है, लेकिन इसके 'केंद्रीकरण' और 'फंडिंग पैटर्न' में बदलाव से ग्रामीण विकास के लोकतांत्रिक आधार को खतरा हो सकता है। भारत के संघीय ढांचे को मजबूत रखने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण नीतियों का केंद्र 'ग्राम सभा' और राज्य ही बने रहें।

प्रिलिम्स प्रैक्टिस प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें – VB-G RAM G बिल के बारे में:

1. यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को प्रतिस्थापित करता है।
2. यह प्रति घर 125 रोजगार दिवस बढ़ाता है।
3. यह मूल MGNREGS की तरह मजदूरी का 100% केंद्रीय वित्त पोषण बनाए रखता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

विकल्प:

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: A. केवल 1 और 2



Q2. VB-G RAM G बिल के खिलाफ

उठाई गई प्रमुख चिंता कौन-सी है?

विकल्प:

- A. यह योजना को पूरी तरह मांग आधारित बनाता है।
- B. यह निर्णय लेने में राज्य की स्वायत्तता बढ़ाता है।
- C. यह वित्तपोषण का पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 कर देता है।
- D. यह प्रति घर 200 से अधिक रोजगार दिवस की गारंटी देता है।

उत्तर: C. यह वित्तपोषण का पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 कर देता है।

मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

प्रश्न: VB-G RAM G बिल प्रशासन, संघवाद और रोजगार सुरक्षा के संदर्भ में मूल MGNREGS से महत्वपूर्ण भिन्नता दर्शाता है। ग्रामीण भारत के लिए इस बिल के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और सुझाव दीजिए कि कैसे यह योजना अपने विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा कर सके। (150 शब्द)

IAS-PCS Institute



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806



www.resultmitra.com